

# न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या  
प्रविष्टि दिनांक

26 / 2020  
05.03.2020

शैतान पुत्र राधेश्याम जाति धोबी निवासी सोप तहसील उनियारा जिला टोंक राज०  
-अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला-टोंक

-रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध

निर्णय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 14.10.2019 मिसल नम्बर 738-40 / 2019

उपस्थिति : (1) श्री योगेश व्यास, अभिभाषक अपीलान्ट

(2) श्री रामप्रसाद कुमावत, नायब तहसीलदार राजकीय परोकार

निर्णय

दिनांक 30.08.2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 14.10.2019 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 3711/2943 रकबा 2.25 है०, खसरा नम्बर 2944/3408 रकबा 0.46 है० व खसरा नम्बर 3711/2943 रकबा 0.03 है० कुल रकबा 2.74 है० किस्म बारानी वाके ग्राम सोप तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर क्रमशः बगीचा, चरी, उडद, बाजरा की फसल काश्त कर एवं दुकानों का निर्माण कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 4084/रू. पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय परोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलान्ट की प्रोपर तामिल नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का से अपीलान्ट को जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया है। पटवारी हल्का ने दुर्भावना पूर्वक उक्त भूमि बाबत रिपोर्ट पेश की है। अपीलान्ट उसके पूर्वजों का उक्त भूमि पर गत 40 वर्षों से भी अधिक समय से कब्जा चला रहा है। अपीलान्ट को पूर्व में कभी भी उक्त भूमि से बेदखल नहीं किया गया है। अपीलान्ट



जिला कलेक्टर  
टोंक

द्वारा उक्त भूमि पर बनी हुई दुकानों में व्यवसाय करके अपना व अपने परिवार का पालन-पोषण करता आ रहा है। अपीलान्त के पास इस भूमि में बनी हुई दुकानों के अलावा आय का कोई अन्य साधन नहीं है। अपीलान्त द्वारा उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार की कोई फसल काशत नहीं की है। मौके पर उक्त भूमि पर वर्तमान में कोई फसल नहीं है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्त के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय परोकार ने कथन किया कि अपीलान्त को विवादित भूमि खसरा नम्बर 3711/2943 रकबा 2.25 है०, खसरा नम्बर 2944/3408 रकबा 0.46 है० व खसरा नम्बर 3711/2943 रकबा 0.03 है० कुल रकबा 2.74 है० किस्म बारानी वाके ग्राम सोप तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर कमशः बगीचा, चरी, उडद, बाजरा की फसल काशत कर एवं दुकानों का निर्माण करने पर नायब तहसीलदार सोप द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम कर 90 दिवस की सिविल कारावास की दजा से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्त की विधिवत तामील हुई है। अपीलान्त न्यायालय में उपस्थित हुये है। अपीलान्त ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एवं बयानों से सिद्ध है। अपीलान्त भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय परोकार की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर तामील हुई है। अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुये है। अपीलान्त द्वारा भूमि खसरा नम्बर 3711/2943 रकबा 2.25 है०, खसरा नम्बर 2944/3408 रकबा 0.46 है० व खसरा नम्बर 3711/2943 रकबा 0.03 है० कुल रकबा 2.74 है० किस्म बारानी वाके ग्राम सोप तहसील उनियारा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर कमशः बगीचा, चरी, उडद, बाजरा की फसल काशत कर एवं दुकानों का निर्माण कर अतिक्रमण किया है, जो पत्रावली में सलंगन प्रमाणित प्रति पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानों से सिद्ध है। अपीलान्त ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं० 99/2018 निर्णय दिनांक 15.11.2018 से भूमि से बेदखल किया गया है। चूंकि उक्त खसरा नम्बर का न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में ही दिनांक 23.12.2020 को निर्णय पारित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में पुनः निर्णय पारित किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

फलतः अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप का निर्णय दिनांक 14.10.2019 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र रथगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



चिन्मयी  
(चिन्मयी गोपाल)  
जिला कलेक्टर  
टोंक